भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 531

दिनांक 3.5.2000 **को उत्तर के लिए**

सामान्य सरकारी पत्राचार में स्थानीय भाषाएं

***531. डा0 राजा रामण्णा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामान्य सरकारी पत्राचार में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग में ह्रास और अंग्रेजी के अध्ययन के लिए छात्रों के वर्धित पंजीकरण को रोकने के लिए कदम उठाएगी;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सामान्य रूप से स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों में अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग से स्थानीय भाषाएं लगभग लुप्त हो रही हैं; और

(ग) क्या कम्प्यूटर बहुविध अनुवाद और अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग आरंभ करके इसे कम किया जा सकता है ?

उत्तर

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी)

(क), (ख) और (ग) : यह सच नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त हो रही हैं । जहां कहीं सम्भव है, क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करने के लिए कम्प्यूटरों और सभी उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है, और वस्तुत इनका प्रयोग किया जा रहा है । भाषा के मामले में, भारत सरकार, संविधान में निर्धारित अपनी जिम्मेवारियों से पूरी तरह अवगत है और सभी आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 531
TO BE ANSWERED ON 3.5.2000

LOCAL LANGUAGES IN NORMAL GOVERNMENT CORRESPONDENCE

***531. DR. RAJA RAMANNA:**

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government would take steps to stop the deterioration of the use of local languages in normal Government correspondence and increased enrolment of students for the study of English;

(b) if not, whether the increased use of English among people normally using local languages is making local languages nearly obsolete; and

(c) can this be reduced by introducing the use of computer multiple translation and other modern devices?

ANSWER

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI)

(a),(b) &(c): It is not true that the local languages are becoming obsolete. Use of computers and all available modern facilities can, and in fact are being used, to promote the local languages, wherever possible. In the matter of language Government of India is fully alive to its responsibilities as laid down in the Constitution and has been taking all necessary action.

*****